1970-2020

४७वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस

28 व 29 नवंबर, 2019

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

समापन समारोह में

माननीय श्री अमित शाह जी

गृहमंत्री, भारत सरकार

का संबोधन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

2019
CE
D DEVELOPMENT

UTTAR PI
AU OF POLICE RE
47TH ALL INDIA POLICE SCIENCE CONGRESS

47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

समापन समारोह में

माननीय श्री अमित शाह जी

गृहमंत्री, भारत सरकार
का संबोधन

'Promoting Good Practices and Standards'

47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

भूमिका

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो प्रतिवर्ष अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस का आयोजन करता है। इस राष्ट्रीय काँग्रेस का उद्देश्य, विभिन्न पुलिस बलों, सामाजिक वैज्ञानिकों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और दूसरे हितधारकों को पुलिस से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह विभिन्न हितधारकों को एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी साझा करने का भी अवसर प्रदान करता है।

प्रथम अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस का आयोजन वर्ष 1960 में, पटना, बिहार, में किया गया था। इस वर्ष 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस का आयोजन, उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से लखनऊ, उत्तर प्रदेश, में दिनांक 28 व 29 नवंबर को किया गया।

47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस के उद्घाटन समारोह में डॉ किरण बेदी, माननीया उपराज्यपाल, पुदुचेरी, मुख्य अतिथि थीं, और समापन सामारोह में मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार, और विशिष्ट अतिथि, श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, थे।

केन्द्रीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह जी के संबोधन से निकली मुख्य बातें

1. आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों के विभिन्न law enforcement agencies के बीच समन्वय की आवश्यकता है। यह समन्वय निचले स्तर तक भी होना चाहिए।
2. पुलिसकर्मियों की शहादत और उनके द्वारा किये गये अच्छे कार्यों का प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि आम जनता के मन में पुलिसकर्मियों के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ सके।
3. पुलिस की सफलता के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के पुलिसकर्मियों का मनोबल ऊँचा हो और सभी team भावना से कार्य करें।
4. IPC और CrPC में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी स्तर पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
5. राष्ट्रीय स्तर पर National Forensic Science University बनाने की आवश्यकता है, ताकि देश में पर्याप्त Forensic Science Expert उपलब्ध हों।
6. सभी राज्यों में Modus Operandi Bureau की स्थापना करने की आवश्यकता है, ताकि एक ही प्रकार के अपराध करने वाले लोगों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही की जा सके।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो देश के समस्त पुलिस संस्थाओं में सुधार के लिए निरंतर कार्यरत है।

(वी.एस.के. कौमुदी)
महानिदेशक
बी.पी.आर. & डी.

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

28 व 29 नवंबर, 2019,

47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉंग्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, के समापन समारोह में
माननीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह जी, का संबोधन

आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। संगठन में लम्बे समय तक मेरे साथी रहे और आज उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व जो निभा रहे हैं ऐसे श्रीमान केशव प्रसाद मौर्या जी। लम्बे समय तक लखनऊ के प्रथम नागरिक के नाते सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के हृदय, लखनऊ, को जिन्होंने संजोया है, ऐसे डॉ दिनेश शर्मा जी, जो आज उप मुख्यमंत्री के नाते उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मुख्य सचिव, श्रीमान आर. के. तिवारी जी, डी.जी.पी., उत्तर प्रदेश, ओपी सिंह जी, डॉ ए.पी. महेश्वरी जी, और हम सब जिनके निमंत्रण पर आज यहां पर आए हैं, BPR&D के डी.जी.,श्रीमान कौमुदी जी, और सभी राज्यों और संघ प्रदेशों से पधारे हुए सभी भाईयों और बहनों।

आज 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉंग्रेस के समापन समारोह कार्यक्रम में आप सबसे मिलकर मुझे अत्यंत हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। पहले भी एक बार मैं जब गुजरात का गृहमंत्री था, तब गांधी नगर में यह कॉंग्रेस आयोजित हुई थी। तब उस वक्त, जो प्रतिनिधि के रूप में आऐ थे, उन सभी सज्जनों और देवियों का स्वागत करने का मुझे मौका मिला था। और आज, मैं आपके सामने, इस कार्यक्रम में देश के गृहमंत्री के नाते उपस्थित हूँ। उस वक्त मैं कई बार सोचता हूँ कि उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से फायदा होता है या समापन समारोह कार्यक्रम में। कई बार, आप जो विचार रखते हो, जब आप की कॉंग्रेस समाप्त हो जाती है, सांईस कॉंग्रेस समाप्त हो जाती है, तो विचारों का क्या उपयोग? समापन के अन्दर की गई बातों का क्या उपयोग? जो कार्यक्रमों के विज्ञान पर अभ्यास कर रहे हैं ऐसे लोगों ने मुझे कई बार कहा। मगर मैं हमेशा मानता हूँ कि समारोह के बाद ही शुरूआत होती है। जो मंथन हुआ है, इसके implementation की शुरूआत समारोह के बाद ही होती है। इसलिए अच्छा समापन समारोह में ही जाना होता है। तो जब मूझे निमंत्रण मिला, तब मैंने भी तय किया था, कि 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉंग्रेस के समारोह में ही मैं जाऊँगा। और ये जो BPR&D का काम है एक दृष्टि से समायोजन का काम है, best practices के exchanges का काम है। समस्याओं को ढूंढ़ने का काम है, समस्याओं के समाधान पर चिंतन करने

का काम है, उसका समाधान ढूंढ़ने का काम है, और जो समाधान ढूंढते हैं वे practical रूप से बीट तक लागू हो इसकी चिंता करने की जिम्मेदारी BPR&D की है। उसके mandate को ध्यान से पढें तो व्याप्त BPR&D के mandate का और BPR&D के सारे वर्ष के काम को नीचे तक पहुंचाने का अगर कोई जरिया है तो मैं मानता हूँ कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस है।

कई सालों से आप, 1960 से लेकर अब तक, ये करते आए हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस सिर्फ इस विषय पर करनी चाहिए कि 1960 से 2019 तक जितने भी resolution पारित किये, जितने भी paper इसमें रखे गये, इनका हुआ क्या? अगर चिंतन ही करते रहेंगे, और इसको circulate ही करते रहेंगे, तो फायदा क्या? एक Science Congress, या तो विशेष पुलिस सांईस काँग्रेस बुलानी चाहिए जिसके अंदर 1960 से 2019 तक जितने भी पेपर यहाँ पढ़े गये हैं या रखे गये हैं, जिस पर विचार–विमर्श हुआ है, जितने विषयों पर R&D करने की जरूरत हुई, R&D हुआ, इसके implementation के part पर क्या हुआ? मैं मानता हूँ, इस पर एक गहन विचार करने की जरूरत है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर internal security भी गृह मंत्रालय का mandate है, मगर केवल भारतीय गृह मंत्रालय का, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का, mandate नहीं है। हमारे संविधान ने federal structure को स्वीकार किया है और law & order की जिम्मेदारी राज्यों पर है। परन्तु internal security को एक holistic approach से अगर देखें तो internal security के अन्दर ढ़ेर सारी चीजें आती हैं– सरहदी सुरक्षा आता है, घुसपैठ आती है, fake currency आता है, cyber हमले आते हैं, हथियारों की, पशुओं की, मानवों की तस्करी आता है, narcotics व्यापार आता है। ढ़ेर सारी चीजें ऐसी आती हैं, जो कि सिर्फ state police नहीं कर सकती। यह coordination के बगैर नहीं हो सकता। भारत के गृह मंत्रालय की भी सीधे जिम्मेदारी है कि, coordinator के रोल की जिम्मेदारी अदा करके, सारे राज्यों के साथ मिलकर, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के बीच में जो समन्वय है, उसको सुचारू रूप से नीचे ले जाएँ।

आज, जब हम सब यहां बैठे हैं तब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि घुसपैठ, narcotics control, नक्सलवाद, आतंकवाद, तीनो प्रकार की तस्करी, fake currency और routine law & order, ये सब करते–करते शायद हम लोगों को भी, जो police force से आते हैं, जो police force के लोग यहाँ बैठे हैं, जो नीति निर्धारण और नेतृत्व का काम करते हैं, उनको भी मालूम नहीं है कि आज जिस सफलता को हम देख रहे हैं उसके अंदर 35 हजार से ज़्यादा जवानों ने अपनी जान गवाई है। अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब जाकर यह देश सुरक्षित हुआ है। तब जाकर हमारी सीमाओं से लेकर अंतिम बीट तक सुरक्षा का अनुभव एक आम नागरिक कर सकता है।

अभी–अभी केन्द्र में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक भव्य पुलिस स्मारक का निर्माण हुआ है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है, गृह सचिव ने, सभी डीजी और Chief Secretary को पत्र लिखा है। क्या ये पुलिस स्मारक को अपने–अपने राज्यों में हम पुलिस चेतना का केन्द्र बना सकते हैं क्या? आप सभी लोग अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर हैं, हमारा दायित्व है कि जनता का पुलिस को देखने का नज़रिया और पुलिस का जनता को देखने का नज़रिया दोनों में बदलाव लाना चाहिए। पुलिस के लिए ठठ्ठा करना, मज़ाक करना बहुत सरल बात है। कोई कार्टून बनाएगा, तो कोई बड़ी तोंद वाला पुलिस दिखा देगा, कोई हिन्दी पिक्चर के अन्दर उसका मज़ाक उड़ा देगा, मगर कोई सेवा ऐसी नहीं है जहां पर 35 हजार से ज्यादा जवानों ने शहादत दी है। इसका गौरव एक–एक constable के अन्दर हम खड़ा कर सकते हैं क्या? देश की 130 करोड़ की जनता को पुलिस को देखने के नज़रिये में देखने में, बदलने में इसका हम उपयोग कर सकते हैं क्या? देश की जनता को यह अनुभूति करानी पड़ेगी कि जब एक भाई अपनी बहन के घर में राखी बन्धवाने के लिए जाता है तो police constable traffic की चिंता करता है। जब आप अपने बच्चों के साथ दीपावली में पटाखे जलाते हो, तो police constable उस दिन भी law & order की चिंता करता है। जब आप आपके परिवार के साथ होली का लुत्फ़ उठाते हो, होली के त्यौहार को मनाते हैं, तब वह चिंता करता है कहीं दंगे तो नहीं हो जाएंगे । minus 43 degree temperature से 43 degree temperature तक की विषम परिस्थितियों के अंदर हमारे अर्धसैनिक बल सीमाओं को संभाल कर रखते हैं। और मैं मानता हूँ कि यह नज़रिया बदलने की जिम्मेदारी यहां पर जो बैठे हैं, देश भर के जो पुलिस अधिकारी बैठे हैं, उनकी है। आप सब उच्चस्थ स्थानों पर बैठे हैं, एक–एक constable के मन में ये गर्व खड़ा करना और राज्य की जनता के, एक–एक व्यक्ति के, एक–एक नागरिक के मन मे पुलिस के प्रति सम्मान की भावना खडा करना, ये हमारा primary दायित्व है। जब तक ये नहीं कर सकते हम internal security को ढंग से नहीं संभाल सकते। ये परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी BPR&D जैसे संगठनों की भी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की घटना हो तो घटना में first respondent की जिम्मदारी पुलिस की होती है। सबसे पहला टकराव पुलिस से होता है और जो first respondent की जिम्मेदारी उठाता है उसके प्रति जनता का सम्मान बनाना ये हमारा primary दायित्व है। आप सब के राज्यों के अन्दर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आप का delegation जाकर मिले। राज्य के जितने भी बच्चों की टूर आती है उसके टूर के नक्शे पर हमारे पुलिस स्मारक का स्थान हो। आप के राज्य के अन्दर सबसे अच्छी जो घटनाएं law & order की, पुलिस के बलिदान वाली हुई हैं, लोगों की बड़ी जानहानि बचाने की हुई है, उनकी एक

documentary बनाकर हम पुलिस स्मारक को भेज सकते हैं। बहुत सारे visitors आते हैं, उनको दिखाने के काम में आती है। हर सप्ताह हम इसको change करके दिखाना चाहते हैं, मगर material नहीं है। अब जितने भी विदेश के महानुभव आते हैं, हम उनका एक visit वहां पर रखें। अभी Uzbekistan के रक्षामंत्री आए थे, गृहमंत्री आए हुए थे, डेढ़ घन्टे तक वे पुलिस स्मारक पर रहे। लंका के राष्ट्रपति भी गये वहां। परन्तु इसको समृद्ध करना, हमारे बलिदान की गाथाओं से, हमारे अच्छे performance की कहानियों से, हमारी best practices से, उसका दायित्व हमारा है। मुझे लगता है हमें इसको करना चाहिए।

मित्रो, internal security का दायरा बहुत लम्बा है। जैसा मैंने आगे कहा, 15 हजार किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीनी सरहद, 7500 किलोमीटर का coastline border है और चारों ओर से भारत को मुश्किल में रखने के जब प्रयास हो रहे हों, तब हमारी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। Internal security भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि 3 बिंदू ऐसे हैं जिनसे internal security को भारत में मजबूत बनाने की जरूरत है। सबसे पहला, 130 करोड़ का market है। Global economy में 130 करोड़ का market स्वाभाविक रूप से ताकतवर destination के रूप में भारत को दुनिया के बाजार के बीच में रखता है। और मोदी जी के आने के बाद, अपने अर्थतंत्र को गति देने की प्रक्रिया चली है। 2004 में, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तालिका में 11वें नंबर पर थी। सिर्फ 5 साल के अंदर 11वें नंबर से 7वें नंबर पर आ गई है। और हमारा लक्ष्य है, 2024 तक इसे 5 trillion dollar की इकॉनामी बनाकर, एक से तीन नंबर के अंदर जाने का हमारा लक्ष्य है। जब हम ये प्रयास करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें रोकने के लिए ढ़ेर सारी शक्तियाँ activate होंगी तो उनका सामना कौन करेगा– हमें करना है। Cyber attack को, fake currency को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है– हमारी है। Cyber attack और fake currency के बड़े–बड़े scams, उसका अच्छा investigation, professional investigation और दण्ड करने की प्रक्रिया का सुधार करना, ये जिम्मेदारी हमारी है । तभी जाकर मोदी जी का जो स्वप्न है, हमारे अर्थतंत्र को गति देने का, वह हम सिद्ध कर पायेंगे। तो पहला कारण है, हमारी internal security को चुस्त और दुरूस्त करने का कि हम 5 trillion dollar की economy बनना चाहते हैं और 130 करोड़ का बाजार आज पूरी दुनिया के लिए एक lucrative centre, आकर्षण का केन्द्र, बना हुआ है। तो यहां कानून और व्यवस्था, internal security, अगर अच्छी नहीं होगी तो ये कभी नहीं हो सकता। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, 15 हजार किलोमीटर की land boundary और 7500 किलोमीटर की coastline और पड़ोसी के बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप सब को मालूम है, मगर पड़ोसी तो हम

बदल नहीं सकते; हमारी चुस्तता में बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी। वहां से जो आतंकवाद के बीज बोए जाते हैं, उसको कोई space न मिले, उसको कोई जगह न मिले। हमारी border security को चुस्त और दुरूस्त करने के लिए, border security पर तैनात अर्धसैनिक बलों और state police के बीच में coordination अभेद्य होना चाहिए, कि हवा भी बीच में से ना जा सके। इस प्रकार का अभेद्य coordination करने की जिम्मेदारी हमारी है। और तीसरा, हमारा देश बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषाएँ, बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारी पहलुओं, से बंधा हुआ है। एक ओर तो हमें इसका गौरव है। हमारे देश की पहचान ही विविधता में एकता की है, परन्तु उसके साथ–साथ vulnerability भी बढ़ती है। दुश्मन को जगह मिलती है। भेद खड़ा करने की, दुश्मन को जगह मिलती है, Cyber attack से अलग अलग प्रकार के मतभेद देश की जनता के बीच खड़े करने की उसकी रोकथाम करना, कठोरता के साथ इसको खत्म करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूँ, ये तीनों चीजों के कारण, हमारी internal security बहुत महत्वपूर्ण बनती है, और बहुत कठिन भी बनती है।

मित्रो, हमारे पास democracy, demography dividend है। और इसीलिए हम भारत की destiny को बदलना चाहते हैं। और मुझे भरोसा है, मोदी जी के नेतृत्व में हम बदल सकते हैं। मगर उसकी पूर्व शर्त है कि 21वीं सदी के भारत की आंतरिक सुरक्षा को हम चुस्त–दुरूस्त रखें और इसके लिए अपने आप को तैयार करें। और वो खाली भारत सरकार नहीं कर सकती। जब तक देश का हर राज्य और संघ प्रदेश एकवाक्यता के साथ इसमें contribute नहीं करता, ये बदल नहीं सकती।

हमारे policing के अंदर भी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। श्री कौमुदी ने मुझे quote करके कहा, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि police reform से ज्यादा policing में reform की जरूरत है। और हमारे reform की दिशा को थोड़ा मोड़ने की जरूरत है। और ये सिर्फ technology से नहीं हो सकता। जब मन नहीं जुडेंगे तो कुछ नहीं होगा। मै इतने बड़े भवन के अंदर आया, UP Police का। मगर भवन के अन्दर अगर काम करने वालों के मन में भावना नहीं है, तो ये भवन कभी भी अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। भवन परिणाम नहीं दे सकते। भवन के अंदर काम करने वालों की भावना ही परिणाम दे सकती हैं। और ये परिवर्तन हमें करना पड़ेगा।

ये Science Congres formality बनकर नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक होनी चाहिए, परिवर्तन की परिचायक बननी चाहिए। और वह तभी बन सकती है, जबकि यहां जो चर्चाएं होती हैं, इसको spirit से बीट तक लागू करने के लिए हम आगे बढें। और मित्रो, मैं आप को बताना चाहता हूँ

कि motivation वाली leadership के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले देश में हर जगह उत्तर प्रदेश के law & order के चर्चे होते थे। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृहमंत्री के नाते, दोनों के नाते, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के law & order को बहुत–बहुत सुधार करके, एक अच्छे राज्य का उदाहरण दिया। एक motivated leadership क्या कर सकती है, इसका एक उदाहरण है और आप और सभी जो यहाँ बैठे हैं, एक प्रकार से लीडर हो, आपके क्षेत्र के लीडर हो। आपके क्षेत्र को leadership देनी है। 50 हजार से 60 हजार का पुलिस बल (मैं एवरेज कह रहा हूँ) उसका leader कौन होता है? Senior most police officer होता है। और, मैं इसीलिए कहता हूँ कि BPR&D की ये इस प्रकार की meeting है जो best practices के आदान प्रदान के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म होती है–अगर हम इसको जारी रखें तो। यहां पर जो पेपर श्रुत हुए हैं, और यहाँ पर जो चीजें कही हैं, इसको spirit के साथ अपने राज्य के अनुकूल जो चीजें हैं, वह बीट तक ले जाने के लिए हम करें। और सफलता तभी मिल सकती है, जब हर राज्य के अंदर constable से लेकर DGP के बीच policing के दृष्टिकोण और policing के implementation के लिए एकवाक्यता होनी चाहिए। एक टीम के नाते, पूरी force काम करे, तभी जाकर हमें सफलता मिल सकती है। मैं मानता हूँ कि इसकी बहुत बड़ी जरूरत है।

मित्रो, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। IPC और CrPC के अन्दर आमूल चूल परिवर्तन का है। Arms Act भी बदल रहे हैं। इसी सत्र के अन्दर, narcotics के बारे में भी कानून में संशोधन कर रहे हैं। और बाद में CrPC और IPC में भी बदलाव लाएंगे। क्योंकि दृष्टिकोण ही अलग हैं, CrPC और IPC की रचना तब हुई थी, जब एक देश जो हमारे पर शासन करता था उसने गुलाम देश पर अपनी कानून और व्यवस्था का शासन करना था। उसकी priority नागरिक नहीं था। उसकी priority हमारा देश नहीं था। उनकी priority अपना शासन चलाना था। अब हम स्वतंत्र हो गये हैं। हमारे अपने नागरिक हैं। वो approach नहीं चलेगी। और जब तक कानून नहीं बदलेगा–CrPC और IPC नहीं बदलेगी–तो approach नहीं बदलेगी। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मानव वध से बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? आप के यहाँ धारा 302 है, लेकिन उससे पहले खजाना लूटना, राज्य के सामने विद्रोह करना, ये सारी दफाएँ आती हैं। तो, priority क्या है? ये इंगित करता है कि ब्रिटिश शासन की तो ये priority हो सकती है, सार्वभौम के साथ,

गौरव के साथ जीने वाले हिंदुस्तान की, भारत की ये priority नहीं हो सकती। हमारी priority देश का गरीब से गरीब व्यक्ति ही है। और इस spirit के साथ अगर इसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सुझाव दीजिए। वैसे तो BPR&D ने अपना बदलाव का मसौदा बनाकर गृह मंत्रालय को भेज दिया है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कीजिए। Police inspector और police sub-inspector तक, जो रोज practically इसका उपयोग करते हैं, वहां से सुझाव आने चाहिए। इसको सरल कैसे बनाएं, इसको सुचारू कैसे बनाएं, इसको लोकान्मुख कैसे बनाएं? इसके अंदर सज़ा सबसे ज्यादा करा पाएँ, इस तरह के प्रावधान कैसे add किया जाए, ये सारी चीजों को देख कर एक complete परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन, रोज़–रोज़ नहीं होते। कभी–कभार, सदी में एकाध बार होते हैं। और मैं मानता हूँ कि आप लोगों को मौका मिला है कि सदी में एक बार जो परिवर्तन होने वाला है, इसके अंदर contribute करने का किसी ने मौका दिया है। ये नीचे से सुझाव मंगाईये, उसके लिए committee बनाईये, इसका screening करिए, इसको दफाओं में, धाराओं में ढालिए और बाद में conclude करके सुझाव भेजिए। मैं मानता हूँ कि इसके अन्दर आप सबने, हर राज्य ने, हर प्रदेश नें, और जिनको अनुभव है, चाहे वो अर्धसैनिक बल में तैनात हों, वो सभी को contribute करना चाहिए। इस पवित्र प्रक्रिया से हमारा CrPC और IPC का परिवर्तन होना चाहिए। बाद में, उसको website पर भी रखने वाले हैं, ढेर सारे वकीलों से भी और ढेर सारे जजों से भी इसके सुझाव मंगाने वाले हैं, बाद में जाकर सरकार निर्णय लेगी। परन्तु मेरा आग्रह है, जो implement करने वाले हैं, वो अगर सुझाव देते हैं तो ये सुझाव बहुत उपयोगी सुझाव होंगे।

दूसरा सबसे बड़ा काम हम करने जा रहे हैं–एक रक्षा शक्ति university बनाने जा रहे हैं–Centre में। और जिन राज्यों में police university नहीं है, वहाँ पर उसकी एक college खुलनी चाहिए, ताकि जिस बच्चे ने तय किया है कि मुझे professional policing में ही जाना है तो उसको बाकी सब पढ़ाने की, सिखाने की, जरूरत है मगर सीमित मात्रा में। उसको पुलिस विषय का विशेषज्ञ बनाने की जरूरत है। तो 10वीं कक्षा के बाद, कोई बच्चा अपना career बना सकता है इस विषय में। हर राज्य में इसकी एक college होगी और central university होगी और उसके अंदर सभी प्रकार की विधाओं को, forensic science को भी, पढाया जाएगा। कानून भी पढ़ाया जाएगा, prosecution भी पढ़ाया जाएगा, investigation भी पढ़ाया जाएगा और पुलिस स्टेशन को कैसे अच्छा रखना, कैसे चलाना, coordination, दूरसंचार ये सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब ये कानून लेकर university की स्थापना भारत

सरकार करे– जहाँ–जहाँ पर भी ऐसी विशेष university नहीं है, university के संलग्न college खोलने के लिए आप लोगों को पूरा योगदान देना है। Facilitation यहाँ की होगी, force यहाँ की होगी, परन्तु एक college आप के राज्य में भी बनाइये, जिससे एक विशेष रूप से तैयार किया हुआ कार्यबल, लंबे समय के बाद, हमारे पास उपलब्ध हो। और उनको नौकरी देने के लिए interview में priority भी दें। जो यहाँ से निकल कर आएगा, क्योंकि वह तो readymade material है, जिसकी training आपको करनी ही नहीं है। और, अगर ये नौकरी बनने का ज़रिया बनता है, तो मैं मानता हूँ कि सभी चाहेंगे कि वे university के अंदर admission लें और एक अच्छा police officer पहले से बनकर वहाँ पर जाएं। मुझे लगता है कि इसमें आप सबने अपने–अपने राज्यों को तैयार भी करना पड़ेगा।

एक दूसरा initiative लेने वाले हैं। National Forensic Science University को बनाने जा रहे हैं। केन्द्र सरकार की मंशा है कि सज़ाओं के अभी जो percentage है, सजा दिलाने का जो पर्सेंटेज है, वो बहुत कम है। Conviction रेट को देखें तो दयनीय है। इसको कैसे अच्छा करें? मैं मानता हूँ कि ढेर सारी कठिनाइयाँ हैं। कोर्ट के अंदर केस सालों साल पड़े रहते हैं। जो investigation करता है, बाद में तो कहीं और चला गया होता है। केस उसको पूरा याद भी नहीं होता है। Prosecution की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। परन्तु हमने क्या प्रयास छोड़ देना चाहिए? जो आदती गुनहगार है, उसको जब तक सज़ा नहीं कराते हैं, तब तक अच्छे लोगों में संदेश जाना असंभव है। और सज़ा करने का प्रमाण हमें बनाना ही पडेगा। और इसीलिए, forensic science को हमने (जिस अपराध में) 7 साल और उससे ज्यादा सजा है, तो इन सब में FSL को compulsory करना है। Circular तो आज ही हो सकता है। मैं कर भी सकता हूँ। आप सब को advisory भी दे सकता हूँ। मगर manforce कहाँ है। FSL के इतने विशेषज्ञ ही नहीं हैं। तो उसको बनाने पडेंगे। हर ज़िले के अंदर एक FSL branch बनानी पड़ेगी। क्षेत्र के अंदर IG तक की जो आप की रेंज होगी। हर राज्य में एक अलग–अलग व्यवस्था है। मगर एक रेंज की जगह पर एक छोटी FSL laboratory और राज्य के मुख्यालय में बड़ी FSL laboratory। और छोटी FSL laboratory, और राज्य में बड़ी forensic science laboratory और trained manpower हों। ये करना है तो forensic science की पढ़ाई–लिखाई किये हुए हमें बच्चे चाहिए, युवा चाहिए। इसलिए हम forensic science university बनाना चाहते हैं। इसमें भी कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक इसकी affiliated college आपके राज्य में खुलनी चाहिए, जो बहुत कम खर्चे में खुल सकती है। किसी कॉलेज को convert भी कर सकते हैं। किसी भी science college को convert भी कर सकते हैं। और मैं

मानता हूँ कि इतना तो आपका प्रभाव है। आप के senior most, पाँच police officer मिलकर, मुख्यमंत्री जी के पास जाएँ और बोलें कि हमें forensic science का एक कॉलेज हम अपने यहां बनाएंगे। मुझे लगता है कि कोई मुख्यमंत्री ना नहीं बोलेगा। क्योंकि, उसकी भी इच्छा है कि अंततोगत्वा राज्य के अंदर अच्छा law & order हो। परन्तु, इसके लिए हमें initiative लेना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि FSL University, हमारा सजा कराने का जो प्रमाण है उसमें बहुत बढ़ोत्तरी करेगा। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसमें भी आप का सहयोग अपेक्षित है और मिलना भी चाहिए ।

मित्रो, narcotics देश की आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है। और, दुर्भाग्य से, इसकी स्थिति ऐसी है कि centre में narcotics bureau, state narcotics bureau, district headquarters police और बीट इसके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। Revenue department भी देखता है, pharmacy वाले भी देखते हैं। ऐसा "गौंधण" करके रख दिया है। जो मराठी है, वह मेरे शब्द का प्रयोग समझ पाएगा। ऐसा "गौंधण" करके रख दिया है कि इसकी सटीक कार्यवाही हो ही नहीं सकती। भारत सरकार इसमें भी सुधार करने जा रही है। Narcotics Bureau के पूरे structure को बदलना चाहिए। मगर, उसके साथ आपके Narcotics Bureau को बीट स्तर तक की व्यवस्था का भी एक model बनाकर हम आपको देंगे। Advisory form में भेजेंगे क्योंकि हमारे संविधान के अंदर हम advisory दे सकते हैं। मगर वह advisory form में जो model आता है उसको आपके राज्य की परिस्थिति के अनुरूप बदलकर जरूर implement करने का प्रयास करें। क्योंकि जिस देश की नस्ल खोखली हो जाती है, वह देश कभी दुनिया का leader नहीं बन सकता। और मैं आपको कहता हूँ, मित्रो–दुनिया का leader बनने का भारत का समय आ गया है। हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए, narcotics पर पूर्ण control होना चाहिए। सारे अर्धसैनिक बल हैं, वो इसको रोकेंगे। उसके raw material की खेती पर भी हम दबाव बनाएँगे। Chemical वाले narcotics हैं, उस पर भी हम अलग कानून लेकर आ रहे हैं। Coordination की व्यवस्था होगी। एक्ट भी कठोर होगा और इसमें prosecution के लिए भी एक trained manpower भी हम राज्यों के लिए देने के लिए सोच रहे हैं। अच्छे वकील भी देंगे, जो इसमें पारंगत हों। एक ही विधा के अन्दर जिन्होंने specialization किया हो। मैंने सभी law university के dean को पत्र लिखा है कि आप के यहां एक अलग डिपार्टमेंट खुलना चाहिए और उसमें specialization करने वाले बच्चों की सूची हमें दें। क्या असंभव है अगर पुलिस ठान ले तो। मैं आप को आज भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मज़ाक उड़ाना है उड़ा ले। आज भी, जितना भी गांव में शोर–शराबा होता है, दंगा होता है, वहाँ पर

दो constable, हाथ में लाठी लेकर पहुंचते हैं, तो लोग कहते हैं, पुलिस आ गई, भागो और शांति हो जाती है। ये credibility आज भी हमारी है। उसको आगे बढ़ाने का काम है। मैंने कई बार देखा है, मेरे सार्वजनिक जीवन में, सिर्फ दो ही constable डंडा लेकर आते हैं और तलवार लेकर दंगा करने वाले भाग जाते हैं, क्योंकि कानून आपके पीछे खड़ा है, व्यवस्था आप के पीछे खड़ी है, न्याय आपके पीछे खड़ा है। और इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और narcotics को control करने के लिए भी आपका सहयोग भारत सरकार को चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपका भी दायित्व है भारत सरकार को सहयोग देने का।

दूसरा Modus Operandi Bureau जब तक नहीं बनाएंगे, हम कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पर control नहीं कर सकते। FIR के registration होने के साथ ही bureau के पास इसकी gist आनी चाहिए। और उसके बाद जब सजा होती है तो इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए। और FSL के psychological department का भी ये दायित्व है कि Modus Operandi Bureau स्थापित करे। एक प्रकार के ही चोरी करने वाले लोग, उसको पकड़ने के लिए क्या व्यवस्था है? एक प्रकार से ही लूट करने वाले लोग, उसको पकड़ने की क्या व्यवस्था है? इस तरह से modus operandi का प्रयोग करके, ढेर सारे गुनाह को होने से पहले रोकने में हमें सफलता मिल सकती है। अगर हम इसका विश्लेषण ही नहीं करेंगे, तो सफलता नहीं मिल सकती। तो Modus Operandi Bureau के विचार को भी मैं चाहूंगा कि कुछ राज्य adopt करें, इसको cultivate करें। और सफलतापूर्वक अपने राज्यों के अन्दर इसको आगे बढाने का प्रयास करें।

एक मेरा दूसरा आग्रह है कि prosecution, Director, Prosecution, की व्यवस्था राज्य स्तर पर करना चाहिए। केस में परिणाम क्यों नहीं आया? सरकारी वकील public prosecutor कितने date मांगते हैं? क्यों date मांगते हैं? जब तक उनकी जवाबदेही तय नहीं करेगा कोई, तब तक केसों में सज़ा होने की कोई संभावना ही नहीं है। और वह तभी हो सकता है जब कोई exclusive Director, Prosecution, के नाते बड़े–बड़े cases में–हत्या है, बलात्कार है, शस्त्र के साथ लूट है, बड़ी धाण हैं, ये सारी चीजों के केसों में सजा हो, इसकी चिंता कोई headquarters पर बैठकर करना चाहिए। और प्रावधान है, कानून में। मगर हम करते नहीं क्योंकि हमें लगता है कि हम पर watch dog है। ये हम पर watch dog नहीं है। जो व्यवस्था को जीर्ण–शीर्ण कर दे, उस पर watch dog है। हम तो नहीं चाहते व्यवस्था जीर्ण–शीर्ण हो । कोर्टों के अंदर हमारा पक्ष रखने वाले क्या कर रहे हैं, इस पर हमारी नजर होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूँ, होनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध

है, सभी लोगों से, आपके राज्यों के अंदर Director, Prosecution, को भी आप अलग प्रकार से initiative लेकर एक institutionalized रूप देने का प्रयास करें। हो सकता है कि दो–तीन साल लगेंगे, पाँच साल लगेंगे, मगर जब भी सफल होगा, आप retire भी हुए होंगे तो आप को संतोष होगा कि, मेरे समय में मैंने जो काम किया था, आज मेरे राज्य की बहूत अच्छी सेवाएँ institution दे रहा है। पूरे भाव के साथ करना चाहिए।

जेलों के मैनुअल का upgradation बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी जिम्मेदारी police force की है। जेल को अलग department बनाने से कुछ नहीं होता। By and large, यह पूरा law & order के दायरे में आता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी police force की है। तो जेलों के manual के upgradation के लिए भी मेरा आप सब से आग्रह है कि एक टीम बनाईये और जल्दी से काम करना चाहिए। छोटी–छोटी चीजों से मेरा समय समाप्त हुआ बहुत hurriedly कह देता हूँ। Weapons, ballistics, traffic and transport, design uniform और बीट को पुनर्जीवित करना, परेड को नियमित करना, खबरी प्रणाली, foot march, community policing, ये सारी चीजों पर नये–नये छोटे–छोटे प्रयोग करने के लिए, नीचे स्तर के अफसरों को हमने promote करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और जो ये नये प्रयोग करता है, एक district में एक नया SP युवा SP, जो बीट प्रणालिका, को पूरी जीवित कर लेता है, तो उसको कुछ–न–कुछ appreciation senior officers की ओर से मिलना चाहिए। कोई अपने जिले के बैंड को ढंग से बना लेता है और हर शनिवार और रविवार को जिले के मुख्यालय के अलग–अलग स्थानों पर पुलिस का बैंड कूच करे बगैर, 10 मिनट तक राष्ट्र भावना वाले गीत बजाकर वापस आ जाए, और वो आकर्षण का केन्द्र बन जाए, घर से अभिभावक अपने बच्चों को लेकर वहाँ खड़े रहते हैं, तो आप मानना कि वह SP ने अच्छा काम किया है। उसको प्रेरणा दीजिए। Dog squad और horse, इन सबकी चिंता करनी चाहिए। इस सबका अपना–अपना एक रोल है। गाड़ी आने से policing मजबूत नहीं होती। Movement fast होता है। पुलिस के पुराने जितने भी अंग–पंग हैं, मैं मानता हूँ कि उनका review, मैं मानता हूँ कि आप के स्तर पर ही करना चाहिए। चंडीगढ पुलिस ने बीट के लिए बहुत अच्छा प्रयोग किया है। इसको और भी अच्छा किया जा सकता है। मेरा आग्रह है कि सभी लोग उसको एक बार देखें। गृह मंत्रालय ने अभी–अभी बहुत सारे initiative लिए हैं। NIA Act में सुधार, UAPA में सुधार किया है। धारा 370 हटाना, रामजन्म भूमि के बाद एक अच्छा कानून और व्यवस्था कायम रखने का परिचय आप सब ने दिया। और कश्मीर के अन्दर इतना बड़ा फैसला आने के बाद भी, आज तक पुलिस की गोली से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैं मानता हूँ कि ये भारतीय पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है। ये

सफलता के दौर को हमें आगे ले जाना है। और सफलता के दौर को आगे ले जाना है तो ढेर सारी चीजें व्यवस्था के लिए हम करने वाले हैं। CrPC और IPC के amendment पर बिल लाने वाले हैं। NRC का implementation करने वाले हैं। CrPC और IPC में आमूल–चूल परिवर्तन करने वाले हैं। FSL university का बिल आएगा। रक्षा शक्ति university पर बिल आएगा। ढेर सारे बिल आएँगे। तो मुझे लगता है, ये बिल तब तक सफल नहीं होते जब तक spirit खड़ा करने का काम यहाँ मेरे सामने जो leader बैठे हैं उनके अंदर नहीं हैं।

मित्रो, मैंने पहले ही कहा कि ऐसा ही दो दिन का सम्मेलन सिर्फ अभी तक के शोध पेपर्स पर और लिए गये निर्णयों पर करना चाहिए। पहले तो problem पर research करना चाहिए, उस पर study paper invite करना चाहिए। इसमें जो सुझाव आए हैं, उनको classify करना चाहिए। उसके आधार पर नीति में परिवर्तन करना चाहिए। उसका trial क्रियान्वयन करना चाहिए। और, बाद में उसको review कर, उसको स्थायी रूप देना चाहिए। ये प्रक्रिया जब तक नहीं करते हैं, ये पिकनिक के अलावा कुछ नहीं होगा। माफ करना मेरे शब्दों को। हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। हर रोज मुख्यमंत्री जी फोन कर देते हैं। हर रोज MLA/MP फोन कर देते हैं। अच्छा, है दो दिन लखनऊ में हैं। तो फोन आएगा तो कह देंगे लखनऊ में हैं। क्या ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए? हमारा उद्देश्य व्यवस्था में सुधार करना है। हमारा उद्देश्य व्यवस्था को परिणामों तक पहुंचाना है। अगर ये हम करना चाहते हैं, तो मैंने जो कहा, research, शोध पेपर, सुझााव नीति में परिवर्तन, इसके क्रियान्वयन, उसका review, और बाद में उसका स्थायित्व। ये अगर हम नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि बहुत परिणामदायी conference नहीं रहेगी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने SMART police की कल्पना की है, आप लोगों तक पहुँचा ही होगा। मगर फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ S से sensitive, M से moral, A से alert, R से responsible, और T से tech-savvy SMART के concept को नीचे constable तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और, मोदी जी की कल्पना का विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत तभी बन सकता है, जब कानून और व्यवस्था अच्छी हो, law & order अच्छा हो और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। इस जिम्मेदारी के बोझ से नहीं मगर इस जिम्मेदारी के दायित्व के भाव को समझ कर हम यहां से जाएँ, ये मेरी प्रार्थना है। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं! धन्यवाद!!

Bureau of Police Research & Development

28th & 29th November, 2019

47th All India Police Science Congress

Lucknow, Uttar Pradesh,

Address Delivered by

Shri Amit Shah

Hon'ble Home Minister,
Government of India

'Promoting Good Practices and Standards'

47th All India Police Science Congress
Lucknow, Uttar Pradesh

Introduction: -

The Bureau of Police Research and Development organises the All India Police Science Congress every year. The objective of this Congress is to provide a common platform to various police forces, social scientists, forensic experts and other stakeholders to deliberate on issues related to policing. It also provides an opportunity to different stakeholders for exchange of best practices.

The first All India Police Science Congress was organized in 1960, at Patna, Bihar. This year, the 47th All India Police Science Congress was organized, in collaboration with the U.P. Police, on the 28 and 29th of November, at Lucknow, Uttar Pradesh.

In the inaugural session of the 47th All India Police Science Congress, Dr. Kiran Bedi, the Hon'ble Lt. Governor of Puducherry was the Chief Guest. For the valedictory session, Shri Amit Shah, Hon'ble Home Minister, Government of India, was the Chief Guest and Shri Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh, was the Guest of Honour.

Main points of the address delivered by Shri Amit Shah, Hon'ble Home Minister, Government of India:

1. There is need for coordination among various law enforcement agencies for strengthening the internal security grid. This coordination should be upto the lowest level.
2. There is need to make the people aware of the sacrifices and the good work of the police personnel, so that trust and respect of public towards police grows.
3. For the success of police, it is essential that their morale remains high and they work with team spirit.
4. There is a need for radical changes in the IPC and the CrPC, for which comprehensive discussions should be held at all levels.
5. It is essential to establish a National Forensic Science University, so that adequate numbers of Forensic Science experts are available.
6. A Modus Operandi Bureau is required in each state, so that stern action may be taken against habitual offenders.

The Bureau of Police Research and Development is continuously working for improvement of all police institutions.

(V.S.K. Kaumudi)
Director General
BPR&D

Bureau of Police Research & Development

28th and 29th November, 2019,

Address Delivered by

Shri Amit Shah

Hon'ble Home Minister

Government of India

Shri Yogi Adityanathji, famous and popular Chief Minister of Uttar Pradesh, present on the stage in today's program, Mr. Keshav Prasad Mauryaji, who has been my partner in the organization for a long time, and who is now serving as the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh,Dr. Dinesh Sharmaji, who has successfully nurtured the heart of Uttar Pradesh, Lucknow, and is at present serving Uttar Pradesh as the Deputy Chief Minister, Chief Secretary, Shri. R. K. Tiwari, DGP, Uttar Pradesh, OP Singh ji, Dr. A.P. Maheshwariji, Shri Kaumudiji, on whose invitation all of us have come here and brothers and sisters from all states and union territories!

Today, at the valedictory function of the 47th All India Police Science Congress, after meeting you, I feel the greatest joy and pleasure. When I was the Home Minister of Gujarat, this Congress was held at Gandhi Nagar. At that time, I had the opportunity to welcome all the gentlemen and ladies who had come as delegates. Today, in this programme, I am present in front of you, as the Home Minister of the country. Many times, I think that it is more beneficial to go to the inaugural program rather than the valedictory function. What is use of ideas,when the Congress is over? What is the use of the things discussed during valediction? But I always believe that it starts only after the ceremony is over. What has been churned, it begins only after the ceremony. Therefore, one has to go to the valedictory function only. So when I got the invitation, I also decided that I will go to the function of the 47th All India Police Science Congress.

The work of BPR&D is of coordination, exchange of best practices, finding the problems, deliberating on the solutions of the problems, finding solutions to

them, and to see that they are applied down to the beat level. I believe that the only platform to share the work of BPR&D, down to the lowest level, is the All India Police Science Congress.

Since 1960, for many years, you have been organising this. I urge all of you that an All India Police Science Congress should be organised to find out and discuss all the resolutions passed from 1960 to 2019. What happened to all the papers presented in them? If we keep on contemplating only, then what is the benefit?

One Science Congress or a Special Science Congress needs to be organised to see, what happened to the issues discussed, papers presented in the Science Congress held since1960, on how many subjects Research and Development was needed, and, if, Research and Development was done, what happened to the implementation part.

I believe, a deeper discussion is required on this issue. Friends, we all know that in our constitution, internal security is also the mandate of the Home Ministry, but it is not the mandate of the Home Ministry of India, only. Our Constitution has accepted federal structure and responsibilities of law and order lie on states. But if internal security is seen in a holistic manner, it comprises many things - border security, infiltration, fake currency, cyber attack, smuggling of arms, and animals and human trafficking. It also includes narcotics trade. There are so many things that only the state police cannot deal with. This cannot be done without coordination. The Home Ministry of India has the direct responsibility to integrate the Internal and external security and coordinate with all the states by playing the role of coordinator.

Today, when we are all sitting here, I want to tell you that, while working on narcotics control, infiltration, naxalism, terrorism, even persons from the police force, who frame the policies, even they do not know that the success,which we are enjoying today, is the result of the highest sacrifice of more than 35000 Jawans. Only then common citizen right from our borders to the last beat feels the sense of security.

Recently, after the arrival of Prime Minister Shri Narendra Modi at the centre, a grand Police Memorial has been constructed. I have written letters to the Chief Ministers, Home Secretaries, DGsP and Chief Secretaries. Can we make this police memorial a centre of police consciousness in our respective states? All of you have many important responsibilities. Our responsibility is that both the public perception of the police and the police perception of the public should change. It is very easy to cut jokes on the police. Someone will make a cartoon, someone will show a policeman with a big belly, someone will make fun in a Hindi film, but there is no service which has sacrificed more than 35 thousand jawans. Can we instil this pride in every single constable? Can we use this to change the perception of 130 crore people of the country toward the police? The people of this country will have to realize that when a brother goes to his sister's house to get rakhi tied, the police constable manages traffic. When you burst crackers with your children in Deepawali, the constable worries about law and order on that day. When you celebrate Holi with your family, then he is anxious that riots should not break out.

Our paramilitary forces guard the borders under extreme conditions, in temperatures ranging from (-) 43 to 43 degrees. And I believe that the responsibility of changing the perception lies with the police officers who are sitting here. All of you sitting in high positions, it is our primary responsibility to instil this pride in the mind of every constable and to instil a sense of respect for the police in the mind of every citizen of the state. We cannot manage internal security effectively till we do this.

It is the responsibility of organizations like BPR&D also to bring this change, because, in case of any kind of incident, police is the first responder. The first confrontation is with the police and it is our prime duty to see that the public respects those who takes the responsibility as the first responder.

Your delegation should meet the Chief Ministers of the states. Our Police Memorial should find a place on the tour map of all the children who come on

excursion from the states. The best police performance pertaining to law & order, and, the sacrifices made by the police, the major acts of saving lives of the people-- we can make documentary on such events and send it to the Police Memorial. Many visitors come to the Police Memorial and this film can be shown to them. Every week, we want to shownew content,by turns, but there is little material. Now, when foreign dignitaries come, we should arrange their visit to the Police Memorial. Recently, the Defence Minister of Uzbekistan had come, the Home Minister had come and spent one and a half hours at the Police Memorial. The President of Sri Lanka also visited it. But, it is our responsibility to enrich it, with the stories of our sacrifices, the stories of our creditable performance, and our best practices. I think, we should do it.

Friends, the scope of internal security is very large. As I said before, we have more than 15000 kilometers of land border, 7500 kilometers of coastline and when efforts are being made from all sides to create trouble for India, we should realise our responsibility. There are 3 points because of which there is a need to strengthen internal security in India.

First of all, there is a market of 130 crore people. In the global economy, the market of 130 crore naturally places India in the centre of the world as a powerful destination. After the arrival of Modji, the process of accelerating the economy has started. In 2004, our economy was at number 11 in the list of world economies. Now, it has moved from number 11 to number 7 within just 5 years. Our target is to make it an economy of 5 trillion dollar by 2024 and place it within the top three economies of the world. When we make these efforts, we should understand that there will be many forces trying to stop us. Then, who will face them? We will have to face them. It is our responsibility to stop cyber attacks and fake currency. It is our responsibility to improve the process of investigation, professional investigation and process of conviction in cases of cyber attack, fake currency and big scams. Only then, will we be able to realise the dream of Modiji to give momentum to our economy. So, the first reason to make our internal security

effective is that we want to become a 5 trillion dollar economy and the market of 130 crore people today remains a centre of great attraction for the whole world. So, if law and order and internal security is not good here, it can never happen.

Secondly, as I have already said, we have land border of 15000 km and coastline of 7500 km and I do not want to comment on our neighbour. You all know, we cannot change our neighbours. But we would need to enhance our alertness,so that, the seeds of terrorism, which are sown from there,do not get any space. In order to strengthen the security on our borders, there should be impenetrable coordination grid between the paramilitary forces deployed on borders and the state police, so that no one can breach it. It is our responsibility to ensure such type of coordination.

And, thirdly, our country has many religions, languages, and cultures. On one hand, we are proud of it as the identity of our country lies in unity in diversity. But along with it, our vulnerability also increases. The enemy finds a place to create differences. Enemy finds scope to create differences amongst people through cyber attack. It is also our responsibility to prevent and eradicate such activities with an iron hand.

I believe, because of these three things, our internal security becomes very important, and also very difficult.

Friends, we have democracy and demographic dividend with which we want to change India's destiny. And I am confident that we can change it under Modiji's leadership. But its prerequisite is that we keep the internal security in the 21st century India strong and prepare ourselves for it. The Government of India cannot do it alone. It cannot change unless all states and union territories of the country are on same page and contribute towards it.

There is also need for major change in our policing. Shri Kaumudi quoted me on this, yet, I want to say that reforms in policing are needed more than police reforms. And the direction of our reform needs to be slightly modified. This cannot be done only with technology. Nothing will happen without meeting of the minds.

I entered this big building of the UP Police; but if there is no enthusiasm in the minds of the people working in this building, this building by itself cannot give good results. Buildings cannot produce results. Only the attitudes of those working in the buildings can yield results. We have to bring in these changes.

This Science congress should not be a mere formality but should be a harbinger of change. It should be a symbol of change. And it can happen only, when the deliberations, that take place here, are applied up to the beat level. Friends, I want to tell you that nothing can be achieved without motivational leadership. Uttar Pradesh is an example of this. Before Yogi Adityanathji became the Chief Minister of Uttar Pradesh, law & order in Uttar Pradesh was being discussed everywhere. And today, as the President of the Bharatiya Janata Party and as the Home Minister of the country, I can proudly say that Yogi Adityanath's government has greatly improved the law & order in Uttar Pradesh, and has made it an example of good state. This is an example of motivational leadership.

Everyone who is sitting here is a leader in his own field. Who is the leader of a police force of 50 thousand to 60 thousand, on an average? It is the senior most police officer. That's why I say that this kind of meeting arranged by the BPR&D is a good platform for exchange of best practices. Let's carry the papers presented here, and the issues discussed here, to the beat level, and adopt them as per requirements of the states. Success can be achieved only when there is a unanimity between the ranks from the constables to the DGP about the approach and implementation of policing. We can achieve success only if the entire force works as a team. I believe it is badly needed.

Friends, the Government of India has taken up a huge task. It is regarding bringing about fundamental changes in the IPC and the CrPC. We will amend the Arms Act also. We are amending the Narcotics law in this session. And later on, we will also amend the IPC and the CrPC. Because, when the IPC and the CrPC were enacted, the country was under a different rule and their aim was to govern their colony. Their priority was not the citizen. Their priority was not our country.

They had to perpetuate their regime. Now, we have become independent. We have our own citizens. This approach will not work. And as long as the law does not change — the IPC and the CrPC not change —the approach will not change.

I want to give a small example. What can be a more heinous crime than human slaughter? You have section 302 (I.P.C.) here, but before that come sections regarding looting of treasury, rebellion against the state. So what is the priority? It indicates that what was the priority for the British rule, cannot be the priority for a sovereign and proud India. Our priority is the poorest of the poor in the country. And, if you wish to bring about changes with this spirit, I want to request you all to give your suggestions. BPR&D has sent its suggestions for changes to the Home Ministry, but I am in no hurry. Let's have wider consultations. Suggestions should come from Police Inspectors and Police Sub-Inspectors who practically use these laws on a daily basis. How do we make it simple and democratic? How to add provisions to achieve higher conviction? Bearing this in mind, a complete change should be effected. Such changes do not happen every day. These changes happen once in a century.

And I believe that you have got a rare opportunity to contribute to this change in a century. Constitute a committee for this, get suggestions from all ranks, do their screening, mould them in sections of laws and furnish your suggestions. I think all of you – in all states and regions, be they deployed in CAPFs – all experienced stakeholders – should contribute. This sacred process should change our Cr.PC and I.P.C. Later, it will be uploaded on the website. Suggestions from lawyers and judges will also be solicited and then government will decide. But I urge that the suggestions given by the implementers will be very useful.

The second big step that we are going to take is setting up of a National Police University. And those states which do not have a police university should have a college, so that students who are committed to joining professional policing do not have to study too much of other subjects. They should be trained to be

police specialists. After the 10th class, a student can adopt it as his/her career. Every state will have its college. There will be a central university in which all genres of policing, like forensic science, prosecution, investigation, coordination, communication, and police station management will be taught. Therefore, I appeal to you that when the Central Govt. sets up the University, you have to fully contribute by setting up colleges affiliated to this university wherever there is no such police university. We will facilitate it from the Centre, but you should set up a college in your states which could provide us specially trained police personnel. And we should give priority to such candidates in the interview. Such candidates will be already trained in policing, and will need short or no training. And if it becomes a source of employment, then I believe that all would like to get admission in this university and pass out as a good police officer. I feel that all of you would need to motivate your states to do it.

We are planning to take yet another initiative. We are going to set up a National Forensic Science University. Our intention is to boost the conviction rate which is pitiable right now. How do we increase the conviction rate? Cases languish for years in the courts. Investigation officer is transferred somewhere else and he does not ever remember the case details. Prosecution system is also not proper. But should we give up our efforts? Unless habitual offenders are punished, good people will not get the message. We will have to work out evidences to get conviction. If we want to forensically examine evidence in all cases involving punishment of more than 7 years, we need to create more Forensic Science Laboratories. Every district should have a forensic science laboratory. The state should have a large forensic science laboratory and trained manpower. If we want to do this, we need youngster trained in forensic science. Therefore, we want to create forensic science university. There is no need to spend any money on it. One of its affiliated colleges should open in your state, which can be done at very little cost. You can also convert an existing science college. The senior most five police officers should go to the Chief Minister and tell him that we want to have a college of forensic science. I think no Chief Minister will ever say no.

Because, he too, wishes that eventually there should be good law & order in the state. But for this, we have to take initiative. And I think that FSL University will greatly enhance the evidence for conviction. We are also going to move forward in this direction. In this regard, your cooperation is required and, I am sure, you will cooperate.

Friends, narcotics ruins the future generations of the country. But, unfortunately, the situation is such that there is no coordination among the central narcotics bureau, the state narcotics bureau, the district headquarters police and the beat. The revenue department and the pharmacy people also supervise this. There is so much chaos that effective action is impossible. The Government of India is going to improve the situation. The entire structure of the Narcotics Bureau needs to be changed. We will give you a model for setting up of the Narcotics Bureau up to the beat level. We will send it in the form of an advisory, because, as per our constitution, the central government can issue an advisory. But you may implement the model in the form of advisory by changing it according to the situation in your state. The country whose youth gets addicted, can never become the leader of the world. Friends, I tell you, the time has come for India to become the leader of the world. No one can stop us. Therefore, there should be complete control over narcotics. All paramilitary forces will also help to stop it. We will also control the cultivation of the raw material. There are substances made of chemicals. We are coming up with a separate law for that. There will be a system of coordination. This law will be stricter and we are also thinking of giving trained manpower for prosecution of such cases to the states as well. We will also give good lawyers, who are proficient in it and have done specialization in the field. I have written a letter to the deans of all the law universities with the request to open a separate department and to give us a list of students who are specializing in it. Nothing is impossible, if the police decides to do something. I want to tell you, let others think what they want to and let them make fun of us. Even today, when something happens in the village and a riot takes place, if two constables arrive with lathies in their hand, people say police has come and run away. Peace is

restored. This is our credibility even today. It is our duty to carry it forward. I have seen many times in my public life, that only two constable come with lathies and rioters with swords run away because the law is behind you, the entire system is backing you, justice is with you. And we should use it.The Government of India also needs your support to control narcotics. I believe, it is your responsibility to cooperate with the Government of India in this.

Secondly, unless we establish the Modus Operandi Bureau, we cannot control the law and order situation. With the registration of the FIR, its gist should come to the bureau. And after conviction, there should be psychological analysis of the criminal. It is the responsibility of the Psychology Department of the FSL to establish the Modus Operandi Bureau. What kind of system is there to catch people who are involved in particular type of stealing? What is the system to catch people who are involved in loot in a particular manner? This way, by analysing the modus operandi, we can succeed in preventing a lot of crime before it happens. If we do not analyse it at all, success cannot be achieved. So some states should adopt the idea of the Modus Operandi Bureau and try to promote it.

My next request is that at the state level there must be the system of the Director of Prosecution. Why did the case not yield results? How many adjournments do public prosecutors ask for? Why do they ask for adjournments? Unless someone fixes their accountability, there is no possibility of conviction in the cases. And that can only happen when there is an exclusive Director of Prosecution. To ensure punishment in important cases of murder, rape, big dacoity, we should analyse them at the headquarters level. Provisions and laws exist but we do not try to do it because we think there is no watch dog over us. There has to be a watch dog over those who destroy the system. We do not want the system to be destroyed. What are our representatives doing in the courts – we should have an eye on them. Should we not? I believe that we should. So my request to all of you is to take initiative and try to institutionalize the position of the Director of Prosecution in your states. It may take two-three years or five years,

but when you succeed, even after you retire, you will be satisfied that the work that I did during my tenure is rendering good service to my state. So we should do it with full dedication.

The upgradation of the Prisons Manual is very important. It is the responsibility of the Police. Making jails a separate department will achieve nothing. By and large, all this comes under the purview of law and order. It is the responsibility of the police force. So I urge all of you to form a team and work quickly for the upgradation of the Jail Manual. I have exhausted my time on these matters. Let me rush through certain points. For experimenting with new things like weapons, ballistics, traffic and transport, designing uniform and reviving the beat, having regular parade, informant system, foot march, community policing, etc, we should promote and motivate junior officers. And any new young SP in a district, who does this new experiment, who revives the beat system, should get some appreciation from senior officers. Someone forms the band in his district and every Saturday and Sunday, without having to march, the police band at different places in the district headquarters, plays patriotic songs for 10 minutes, and that becomes the center of attraction– you may take it that the SP has done a good job, if parents stand there with their children. He deserves encouragement. Dog squads and mounted contingents – we should take care of them. All have their own role. Policing does not get stronger simply with the arrival of a vehicle, only movement become faster. I believe that whatever old wings of the police are there, they should all be reviewed at your level. Chandigarh Police has done a very good experiment regarding the beat system. This can be done even better. I urge everyone to see it once.

The Home Ministry has taken a lot of initiatives recently. The NIA Act and the UAPA have been amended. After removal of Article 370 and the Ram Janmabhoomi judgement, all of you have maintained law and order well. Even after such a big decision in Kashmir, till date, not a single person has died from police bullet. Me. I believe that this is the biggest success of the Indian Police.

We have to extend this phase of success further. We are going to do a lot of things for the system. Bill on amendment to CrPC and IPC will be brought. We are going to implement NRC. CrPC and IPC are about to undergo radical changes. Bill for FSL university will come. A bill on Raksha Shakti University will be brought. A lot of bills will be brought. I think these bills will do nothing until the leaders, who are sitting here in front of me, get motivated.

Friends, I have already said that such a two-day conference should be held especially on the research papers and decisions taken so far in the previous Congresses. First of all, you should conduct research on the problems and invite study paper on it. The suggestions which come from it, should be classified. Changes in policy should be made based on that. Their trial should be held and, after reviewing the result, it should be made permanent. Unless you follow this process, this will remain nothing except a picnic. I am sorry for my words. When you are in the district, there is always tension. Everyday Chief Minister makes calls, MLAs/MPs make calls every day. It is good that we are in Lucknow for two days. If I get a call, I will say, I am in Lucknow. Should this be our objective? Our aim is to improve the system and to achieve results. If this is what we want, then, as I said, research, research paper, changes in policy, its implementation, its review, and later its sustainability, should be our aims. If we do not do this, I think, this Conference will not be very meaningful. The vision of our Prime Minister of about SMART police must have reached you. But once again I wish to tell you - S for sensitive, M for moral, A for alert, R for responsible and T for tech – savvy. It is our responsibility to convey the concept of SMART policing upto the constable level. India can become world leader, as imagined by Modiji, only when Law & Order is good, and this responsibility rests on all of us. I urge you to go back with realisation of this responsibility and not consider it as a burden. Best wishes to all of you! Thank you!!

2019
CE
D DEVELOPMENT

UTTAR P
AU OF POLICE RE
47TH ALL INDIA POLICE SCIENCE CONGRESS

POLICE SCIENCE CONGRESS
NOVEMBER 28-29,2019

47TH ALL INDIA POLICE SCIENCE CONGR